अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका
ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 04, (Oct-Dec 2025)

उत्तर प्रदेश के छात्र नेताओं के योगदान का विश्लेषण

डॉ॰ महीपाल सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि अध्ययन संस्थान,
चौ॰ चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ

सचिन कुमार
शोधार्थी, इतिहास विभाग,
चौ॰ चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ

सार

1905 से 1947 के बीच का काल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी अवधि में छात्र आंदोलन एक सशक्त राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। यह शोध पत्र–पत्र उत्तर प्रदेश के छात्र नेताओं के योगदान का विश्लेषण करता है, जो स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण चरणों में अग्रिम पंक्ति में सक्रिय रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे संस्थान राष्ट्रीय चेतना और छात्र राजनीति के केंद्र बने, जहाँ से अनेक प्रभावशाली छात्र नेता तैयार हुए।

इस शोध पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश के छात्रों ने सत्याग्रह, धरने, बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों के दहन, जेल यात्राओं और भूमिगत गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। कई छात्र नेता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) और कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप जैसे क्रांतिकारी संगठनों से भी जुड़े, जिससे छात्र आंदोलनों को वैचारिक गहराई और उग्रता मिली। साथ ही छात्रों ने सामाजिक सुधार आंदोलनों, राष्ट्रीय साहित्य के प्रसार, पर्चे वितरण और स्वदेशी शिक्षा संस्थानों के विकास में भी प्रमुख भूमिका निभाई।

विशेष रूप से, यही छात्र राजनीति आगे चलकर स्वतंत्र भारत के कई प्रमुख नेताओं की आधारभूमि बनी–जैसे लाल बहादुर शास्त्री, पुरुषोत्तम दास टंडन, नारायण दत्त तिवारी और कमलापति त्रिपाठी। इस प्रकार, 1905–1947 के दौरान उत्तर प्रदेश के छात्र आंदोलनों ने न केवल स्वतंत्रता संघर्ष को गति दी, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक नेतृत्व और सामाजिक–राजनीतिक रूपांतरण की नींव भी रखी।

मुख्य शब्द: उत्तर प्रदेश, नेतृत्व निर्माण, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, छात्र नेता, क्रांतिकारी संगठन, स्वतंत्रता संग्राम।

प्रस्तावना

1905 से 1947 के बीच भारत का राष्ट्रीय आंदोलन निरंतर संघर्ष, जनजागरण और राजनीतिक चेतना के विस्तृत प्रसार का काल रहा। यही वह समय था जब स्वतंत्रता की लड़ाई केवल राजनीतिक नेताओं तक सीमित न रहकर विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक पहुँच गई। विशेषकर छात्र समुदाय राष्ट्रीय आंदोलन का एक शक्तिशाली अग्रदूत बनकर उभरा। जैसा कि विपिन चंद्रा ने लिखा है– "बीसवीं सदी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र जन–आंदोलन का रूप ले चुका था, और छात्रों ने इसमें सबसे सक्रिय भूमिका निभाई।"[1] यह तथ्य स्पष्ट करता है कि छात्र शक्ति राजनीतिक परिवर्तनों की मुख्य वाहक बन गई थी। 1905–1947 का इतिहास स्वदेशी आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा, और भारत छोड़ो आंदोलन जैसी अनेक राष्ट्रीय घटनाओं से निर्मित हुआ। इन आंदोलनों ने न केवल जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किया बल्कि युवाओं और छात्रों को भी राष्ट्रवाद की मुख्यधारा में लाया। आर.सी. मजूमदार के अनुसार– "स्वदेशी आंदोलन ने पहली बार छात्रों को संगठित रूप से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सक्रिय किया"।[2] यह काल छात्र नेतृत्व के विकास के लिए आधारभूमि बना।

उत्तर प्रदेश इस राजनीतिक उफान का सबसे प्रभावशाली केंद्र था। प्रयाग (इलाहाबाद), वाराणसी और अलीगढ़ जैसे शहर भारत की बौद्धिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को "पूर्व का ऑक्सफोर्ड" कहा गया, जहाँ से अनेक राष्ट्रीय नेता निकले। बी.आर. नंदा लिखते हैं–"इलाहाबाद विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ ने राष्ट्रीय चेतना को संगठित करने में अद्वितीय भूमिका निभाई।"[3] वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मुस्लिम छात्रों के राजनीतिक उभार का केंद्र था, जहाँ युवा छात्रों ने खिलाफत आंदोलन व असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। छात्र आंदोलन का महत्व केवल तत्कालीन राजनीतिक हलचलों तक सीमित नहीं था; बल्कि इसने भविष्य के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्माण में मौलिक योगदान दिया। इस काल में सक्रिय कई छात्र आगे चलकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और प्रमुख सामाजिक नेता बने। अतः 1905–1947 के छात्र आंदोलनों और उत्तर प्रदेश में उभरते छात्र नेतृत्व का अध्ययन न केवल स्वतंत्रता आंदोलन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारतीय लोकतंत्र में नेतृत्व निर्माण की जड़ें कहाँ और कैसे विकसित हुईं।

1905–1920: स्वदेशी आंदोलन और छात्र सक्रियता

1905 में लॉर्ड कर्ज़न द्वारा बंग-भंग की घोषणा ने भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को तीव्र गति से प्रज्वलित किया। स्वदेशी आंदोलन, जिसने विदेशी वस्त्रों, वस्तुओं और ब्रिटिश संस्थागत नियंत्रण के बहिष्कार का मार्ग अपनाया, उत्तर भारत के छात्रों के लिए राजनीतिक चेतना का प्रारंभिक स्रोत बना। विपिन चंद्रा लिखते हैं–"बंग-भंग ने पहली बार छात्रों को संगठित राष्ट्रीय प्रतिरोध का सक्रिय भाग बनाया।"[4] इस आंदोलन की लपटें शीघ्र ही उत्तर प्रदेश तक पहुँचीं जहाँ इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 04, (Oct-Dec 2025)

और अलीगढ़ प्रमुख केंद्र बने। उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का प्रसार मुख्यतः वैचारिक नेतृत्व और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों के माध्यम से हुआ। वाराणसी, इलाहाबाद और प्रयाग की शैक्षिक संस्थाएँ पहले से ही राष्ट्रवादी बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र थीं। विदेशी वस्त्रों के दहन, ब्रिटिश सामान के बहिष्कार और अंग्रेज़ी शासन के विरोध में छात्रों ने बड़ी रैलियाँ निकालीं। आर.सी. मजूमदार लिखते हैं–"प्रयाग और काशी के विद्यार्थी स्वदेशी आंदोलन की आत्मा बनकर उभरे, जिन्होंने राष्ट्रीय आत्मसम्मान को जन-स्तर तक पहुँचाया।"[5]

स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रवादी शिक्षा के प्रचार को विशेष बल प्रदान किया। विदेशी संस्थानों के बहिष्कार के प्रतिकार में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित हुए, जैसे–काशी विद्यापीठ (1916) तथा राष्ट्रीय विद्यालय। पं. मदन मोहन मालवीय, जो एक प्रेरक व्यक्तित्व थे, ने काशी विद्यापीठ और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि बी.आर. नंदा लिखते हैं–"मालवीय ने शिक्षा को राष्ट्रनिर्माण का हथियार बताया और छात्रों को स्वदेशी चेतना से प्रेरित किया।"[6]

इस काल में छात्र सभाएँ, विद्यार्थी परिषद और गुप्त राजनीतिक बैठकें बढ़ने लगीं। छात्रों ने 'विद्यार्थी परिषद' जैसे संगठनों के माध्यम से बहिष्कार आंदोलन, जनसभा संचालन, तथा राष्ट्रीय गीतों के प्रचार को संगठित रूप दिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (तब का मोहम्मदान एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज) के छात्र संगठनों ने मुस्लिम युवाओं में राष्ट्रीय चेतना को प्रबल किया। मिनॉल्ट के अनुसार–"अलीगढ़ के छात्रों ने स्वदेशी विचार को मुस्लिम समाज के राजनीतिक पुनर्जागरण से जोड़ा।"[7]

इस प्रकार 1905–1920 का काल उत्तर प्रदेश में छात्र राजनीति की वैचारिक नींव बनाने वाला महत्वपूर्ण दौर था। छात्रों की सक्रियता ने आने वाले आंदोलनों–असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो–के लिए नेतृत्व तैयार किया।

1920–1930: असहयोग और खिलाफत आंदोलनों में छात्रों की भूमिका

1920 में गांधीजी द्वारा असहयोग आंदोलन की घोषणा ने छात्र राजनीति को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। गांधीजी ने अपील की कि छात्र ब्रिटिश समर्थित विद्यालयों और विश्वविद्यालयों को छोड़कर राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में दाख़िला लें। इसने उत्तर प्रदेश की छात्र राजनीति में उबाल ला दिया। जूडिथ ब्राउन लिखती हैं–"असहयोग आंदोलन ने छात्रों के जीवन को पूरी तरह राजनीतिक बना दिया।"[8]

सरकारी संस्थानों का त्याग असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा छात्र योगदान था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ कॉलेज, लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और कई अन्य कॉलेजों में छात्रों ने सामूहिक रूप से कक्षाएँ बहिष्कृत कीं। अनेक छात्रों ने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों–जैसे काशी विद्यापीठ और जामिया मिल्लिया इस्लामिया–का रुख किया। इलाहाबाद, वाराणसी, अलीगढ़ और लखनऊ इस काल में छात्र आंदोलनों के प्रमुख केंद्र थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 04, (Oct-Dec 2025)

छात्र आंदोलनों ने बड़े स्तर पर सभाओं, जुलूसों और हड़तालों का नेतृत्व किया। पंडित पुरुषोत्तम दास टंडन ने छात्रों को भाषणों और सभाओं के माध्यम से प्रेरित किया। आर.सी. मजूमदार लिखते हैं– "टंडन युवा छात्रों के लिए एक नैतिक प्रेरणा थे, जिन्होंने असहयोग की धार को तीक्ष्ण किया।"[9]

खिलाफत आंदोलन ने मुस्लिम छात्रों को भी राष्ट्रवादी प्रवाह से जोड़ा। अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों ने खिलाफत समितियों का गठन किया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगाए और असहयोग आंदोलन को गति दी। मिंच के अनुसार–"अलीगढ़ के छात्र नेतृत्व ने पहली बार हिंदू–मुस्लिम एकता को वास्तविक धरातल पर उतारा।"[10]

जवाहरलाल नेहरू का छात्र संगठनों से जुड़ाव भी इसी काल में बढ़ा। नेहरू ने इलाहाबाद और काशी में छात्रों को संबोधित किया और उन्हें सत्याग्रह तथा जनआंदोलन की प्रेरणा दी। नेहरू स्वयं लिखते हैं– "असहयोग आंदोलन में छात्रों की भागीदारी ने राष्ट्रीय संघर्ष का स्वरूप बदल दिया।"[11]

इस दशक में छात्रों ने–

- विदेशी कपड़ों के बहिष्कार
- शराब की दुकानों का पिकेटिंग
- सत्याग्रह मार्च
- पुलिस दमन के विरुद्ध प्रतिरोध
- राष्ट्रीय विद्यालयों के लिए धन संग्रह
- जैसी कार्रवाइयों को बड़े पैमाने पर संगठित किया।

अलीगढ़, इलाहाबाद और काशी में छात्र परिषदों की स्थापना हुई, जिन्होंने नेतृत्व निर्माण के लिए एक संगठित ढांचा प्रदान किया। इस काल में कई ऐसे नेता उभरे जिन्होंने बाद में स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्र भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

1930–1940: सविनय अवज्ञा आंदोलन और छात्र आंदोलन का उभार

1930 का दशक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निर्णायक मोड़ था। नमक सत्याग्रह ने भारतीय जनता और विशेष रूप से युवाओं को अभूतपूर्व राजनीतिक ऊर्जा प्रदान की। महात्मा गांधी की डांडी यात्रा और नमक कानून तोड़ने की अपील ने छात्रों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संगठित रूप से खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि बिपिन चंद्रा लिखते हैं–"नमक सत्याग्रह ने युवाओं और छात्रों को यह विश्वास दिया कि सामान्य जन भी साम्राज्यवादी शासन को चुनौती दे सकते हैं।"[12] इस आंदोलन का प्रभाव उत्तर प्रदेश के शैक्षिक केंद्रों–इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ और अलीगढ़– पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस काल में छात्र राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। यहाँ छात्रों ने सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सभाएँ कीं, धरने दिए, जुलूस निकाले और

नमक कानून के विरुद्ध सार्वजनिक विरोध किया। विश्वविद्यालय के छात्र न केवल स्थानीय आंदोलनों में बल्कि राष्ट्रीय आंदोलनों में भी सहायक बने। बी. आर. नंदा के अनुसार–"इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 1930 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक दिशा दी और नेतृत्व निर्माण का उर्वर केंद्र बना।"[13]

इस दशक में N.S.S. (National Student Service) और विभिन्न छात्र संघों का गठन छात्र राजनीति के औपचारिक रूप को स्थापित करने में महत्वपूर्ण रहा। इन संगठनों ने छात्रों को वैचारिक शिक्षा, संगठनात्मक कौशल, नेतृत्व प्रशिक्षण और राजनीतिक दृष्टिकोण प्रदान किया। विद्यार्थी परिषदों और छात्र संघों ने स्कूलों और कॉलेजों में राष्ट्रीय चेतना फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाई। 1930 के दशक में छात्रों की गतिविधियों ने 'भारत छोड़ो आंदोलन' की पूर्वभूमि तैयार की। क्रांतिकारी साहित्य का वितरण, पुलिस दमन के विरुद्ध प्रदर्शन, ब्रिटिश-समर्थित शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार और ग्रामीण इलाकों में राष्ट्रीय संदेश पहुँचाने जैसे प्रयास छात्रों ने ही किए। आर.सी. मजूमदार इस संदर्भ में लिखते हैं–"सन 1930 के बाद छात्रों ने जिस संगठित ढंग से राजनीतिक जागरण फैलाया, उसी ने 1942 में उनका केंद्रीय नेतृत्व तैयार किया।"[14]

इस दशक के प्रमुख छात्र नेताओं में लाल बहादुर शास्त्री, अचल सिंह, केदारनाथ, नारायण दत्त तिवारी और महादेव प्रसाद जैसे नाम उल्लेखनीय हैं। शास्त्री ने काशी में छात्र सभाओं में भाग लेकर नेतृत्व का प्रारंभिक प्रशिक्षण लिया। नारायण दत्त तिवारी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र नेता के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। अम्मार रिज़वी और अन्य स्थानीय नेताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय चेतना फैलाने में योगदान दिया। इस प्रकार 1930–1940 का दशक उत्तर प्रदेश में छात्र आंदोलन के संगठित रूप, वैचारिक परिपक्वता और नेतृत्व निर्माण का स्वर्णिम दौर साबित हुआ।

1940–1947: भारत छोड़ो आंदोलन और छात्र नेतृत्व का चरम

1940–1947 का काल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का उत्कर्ष-काल था और छात्रों ने इस संघर्ष को निर्णायक दिशा प्रदान की। विशेषकर भारत छोड़ो आंदोलन (1942) में छात्रों ने अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व संभाला। अगस्त क्रांति के समय गांधीजी के "करो या मरो" के नारे ने देशभर के युवाओं को अभूतपूर्व उत्साह और संघर्ष शक्ति प्रदान की। बिपिन चंद्रा लिखते हैं–"भारत छोड़ो आंदोलन में छात्रों ने वह भूमिका निभाई जिसे किसी भी अन्य वर्ग ने इतनी निरंतरता और साहस के साथ नहीं निभाई।"[15]

अगस्त 1942 के बाद ब्रिटिश शासन ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर दिया, जिसके बाद छात्र आंदोलन पूर्ण रूप से भूमिगत रूप में चला। छात्रों ने–

- गुप्त संदेश तंत्र तैयार किए
- पुलिस और सरकारी दफ्तरों पर पर्चे बाँटे
- टेलीफोन व तार-सेवाओं में बाधाएँ पहुँचाईं
- जनसभाओं का संचालन किया

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 04, (Oct-Dec 2025)

- **भूमिगत प्रेस चलाई**

आर.सी. मजूमदार का कहना है–"छात्र संगठन पुलिस राज्य के बीच स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संचार की रीढ़ बने।"[16]

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, बनारस और लखनऊ छात्र संघर्ष के मुख्य केंद्र बने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने भूमिगत नेटवर्क स्थापित किए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने सामूहिक सत्याग्रह किया, और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने ब्रिटिश प्रशासन पर निरंतर दबाव बनाया। वाराणसी और इलाहाबाद में छात्रों के समूहों ने रेलवे स्टेशनों, पुलिस थानों और सरकारी कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किए। अलीगढ़ और काशी के छात्र नेताओं पर पुलिस दमन अत्यधिक हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के युवा–जो पहले खिलाफत आंदोलन में सक्रिय थे–अब "छात्र स्वयंसेवक दल" बना कर भूमिगत गतिविधियों में शामिल हुए। कई छात्रों पर मुकदमे चले, कुछ जेल में बंद किए गए और कई हिंसक दमन का शिकार हुए। पीटर हार्डी के अनुसार–"अलीगढ़ के मुस्लिम छात्रों ने 1942 **में देशव्यापी आंदोलन को सांप्रदायिक सीमाओं से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय स्वरूप दिया।"**[17]

प्रमुख छात्र नेता– नारायण दत्त तिवारी, कमलापति त्रिपाठी, अयोध्यानाथ सिंह ने संघर्ष के दौरान सक्रिय नेतृत्व किया। तिवारी ने भूमिगत प्रेस संगठित किया, कमलापति त्रिपाठी ने पूर्वांचल में छात्रों को संगठित किया और अयोध्यानाथ सिंह ने बनारस में भूमिगत आंदोलन को गति दी, अजब सिंह ने मेरठ जनपद में कॉलेजों के छात्रों को संगठित कर प्रतिदिन होने वाले प्रदर्शनों में भाग लिया और आन्दोलन में सक्रिय भूमिका अदा की। मुस्लिम छात्र संघ के कई उभरते युवा नेताओं ने हिंदू–मुस्लिम एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1940–1947 **का काल छात्र नेतृत्व का चरम इसलिए भी था क्योंकि इस समय के छात्र नेता आगे चलकर स्वतंत्र भारत की राजनीति के शिल्पकार बने। नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री, कमलापति त्रिपाठी केंद्रीय मंत्री, और महादेव प्रसाद संसदीय नेता बने। इस काल के छात्र आंदोलनों ने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी, बल्कि स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक नेतृत्व को भी आकार दिया।**

उत्तर प्रदेश के छात्र नेताओं का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान

उत्तर प्रदेश के छात्र नेताओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जिस प्रकार का योगदान दिया, वह न केवल क्षेत्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण था, बल्कि उसने अखिल भारतीय स्तर पर भी नेतृत्व और दिशा प्रदान की। स्वतंत्रता आंदोलन का हर चरण–सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो–इन छात्र नेताओं के प्रत्यक्ष और सक्रिय योगदान से सशक्त हुआ। विशेष रूप से सत्याग्रह, जेल यात्राएँ और भूमिगत गतिविधियों में उत्तर प्रदेश के छात्र अग्रिम पंक्ति में रहे। इलाहाबाद, बनारस और

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 04, (Oct-Dec 2025)

लखनऊ के छात्रों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध धरने, बहिष्कार अभियान, विदेशी वस्त्रों के दहन, और सरकारी संस्थानों के विरोध में संघर्ष चलाया। कई छात्र नेताओं ने सत्याग्रह के दौरान लंबी जेल यात्राएँ कीं, जिससे राष्ट्रीय चेतना और दृढ़ता का विस्तार हुआ। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश के अनेक छात्र नेताओं ने क्रांतिकारी संगठनों–जैसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) और कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप (CSG)–से भी संबंध स्थापित किए। इलाहाबाद और कानपुर जैसे शहर क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे, जहाँ छात्रों ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफ़ाक उल्ला खाँ और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे नेताओं के साथ वैचारिक एकता दिखाई। छात्र नेताओं ने गुप्त बैठकों, हथियारों की आपूर्ति, संदेशों के आदान-प्रदान और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेस, प्रचार और राष्ट्रीय चिंतन का प्रसार भी उत्तर प्रदेश के छात्र नेताओं के योगदान का महत्वपूर्ण पक्ष था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे केंद्रों से छात्रों ने हस्तलिखित पत्रिकाएँ, पर्चे और विरोध-पत्र तैयार किए, जिन्हें वे गुप्त रूप से बाँटते थे। इस साहित्य ने राष्ट्रीय चेतना को गहराई से प्रभावित किया। कई छात्र भूमिगत प्रेस से जुड़े और फ़रार नेताओं तक संदेश पहुँचाने का काम करते रहे।

सामाजिक स्तर पर भी उत्तर प्रदेश के छात्र नेताओं ने सामाजिक सुधार आंदोलनों–दहेज विरोध, छुआछूत उन्मूलन, महिला शिक्षा, स्वदेशी उद्योगों के समर्थन और शराबबंदी–में सक्रिय भूमिका निभाई। यह नेतृत्व केवल राजनीतिक ही नहीं था, बल्कि सामाजिक पुनर्रचना की दिशा में भी महत्वपूर्ण था। इन सबके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के कई छात्र नेता आगे चलकर अखिल भारतीय नेतृत्व के रूप में उभरे। लाल बहादुर शास्त्री, नारायण दत्त तिवारी, कमलापति त्रिपाठी, अयोध्यानाथ सिंह, पुरुषोत्तम दास टंडन और कई अन्य नेताओं ने विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से ही अपने नेतृत्व की शुरुआत की थी। उनके छात्र जीवन के अनुभवों ने ही भविष्योन्मुख भारतीय राजनीति को स्थिर, नैतिक और जनकेन्द्रित दिशा प्रदान की। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश के छात्र नेताओं का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन की रीढ़ साबित हुआ–राजनीतिक संघर्ष, क्रांतिकारी गतिविधि, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय नेतृत्व–सभी क्षेत्रों में।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में 1905 से 1947 तक सक्रिय छात्र आंदोलनों और छात्र नेताओं का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अवधि में छात्रों ने न केवल राजनीतिक जागृति के वाहक के रूप में बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्माण केंद्र के रूप में भी प्रमुख भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन से लेकर असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका
ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 04, (Oct-Dec 2025)

तक–प्रत्येक चरण में उत्तर प्रदेश के छात्रों ने जिस साहस, ऊर्जा और नैतिक प्रतिबद्धता के साथ भाग लिया, उसने संघर्ष की दिशा और व्यापकता को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ और अलीगढ़ जैसे शहर छात्र राजनीति के बौद्धिक और क्रांतिकारी केंद्र बने, जहाँ से अनेक छात्र नेता उभरे जिन्होंने आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया।

छात्र नेताओं ने सत्याग्रह, जेल यात्राओं, बहिष्कार आंदोलनों और भूमिगत गतिविधियों में अपने अद्वितीय योगदान से ब्रिटिश शासन को निरंतर चुनौती दी। वहीं, क्रांतिकारी गतिविधियों में भी उत्तर प्रदेश के छात्रों की भागीदारी उल्लेखनीय रही–HSRA **और कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप जैसे संगठनों से उनका जुड़ाव स्वतंत्रता आंदोलन की उग्र धाराओं को दिशा देने वाला था। इसके साथ ही, छात्र नेताओं द्वारा प्रेस, प्रचार, पर्चे वितरण और सामाजिक सुधार अभियानों में निभाई गई भूमिका ने जनता को जागरूक करने और राष्ट्रीय चेतना को व्यापक जनसमूह तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसी छात्र राजनीति ने स्वतंत्र भारत के कई शीर्ष नेताओं को जन्म दिया–लाल बहादुर शास्त्री, नारायण दत्त तिवारी, कमलापति त्रिपाठी, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे नेता छात्र जीवन से ही उभरकर सामने आए। इससे सिद्ध होता है कि छात्र आंदोलन केवल तत्कालीन राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वे दीर्घकालिक नेतृत्व निर्माण की प्रक्रिया का आधार स्तंभ भी थे। अतः यह निष्कर्ष स्पष्ट है कि** 1905–1947 **के बीच उत्तर प्रदेश के छात्र आंदोलनों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जा, नेतृत्व और वैचारिक दिशा प्रदान की और भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को आकार देने में अमूल्य भूमिका निभाई।**

संदर्भ

1. चंद्रा, विपिन, इंडियाज़ स्ट्रगल फ़ॉर इंडिपेन्डेन्स, पेंगुइन पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1988, पृ. 112
2. मजूमदार, आर.सी., हिस्ट्री ऑफ़ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, मुंशीराम मनोहरलाल, नई दिल्ली, 1957, पृ. 243
3. नंदा, बी.आर., मेकर्स ऑफ़ मॉडर्न इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1985, पृ. 167
4. चंद्रा, विपिन, इंडियाज़ स्ट्रगल फ़ॉर इंडिपेन्डेन्स, पेंगुइन, नई दिल्ली, 1988, पृ. 130
5. मजूमदार, आर.सी., हिस्ट्री ऑफ़ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, मुंशीराम मनोहरलाल, नई दिल्ली, 1957, पृ. 256
6. नंदा, बी.आर., मेकर्स ऑफ़ मॉडर्न इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1985, पृ. 172
7. मिनॉल्ट, गेल, द खिलाफ़त मूवमेंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 1982, पृ. 44
8. ब्राउन, जूडिथ, गांधी'ज़ राइज़ टू पावर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 1972, पृ. 160
9. मजूमदार, आर.सी., हिस्ट्री ऑफ़ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, 1957, पृ. 289
10. हार्डी, पीटर, द मुसलिम्स ऑफ़ ब्रिटिश इंडिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 1972, पृ. 113
11. नेहरू, जवाहरलाल, द डिस्कवरी ऑफ़ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बंबई, 1946, पृ. 98
12. चंद्रा, विपिन, इंडियाज़ स्ट्रगल फ़ॉर इंडिपेन्डेन्स, पेंगुइन, नई दिल्ली, 1988, पृ. 220
13. नंदा, बी.आर., मेकर्स ऑफ़ मॉडर्न इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1985, पृ. 184
14. मजूमदार, आर.सी., हिस्ट्री ऑफ़ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, मुंशीराम मनोहरलाल, नई दिल्ली, 1957, पृ. 311
15. चंद्रा, विपिन, इंडिया आफ्टर इंडिपेन्डेन्स, पेंगुइन, नई दिल्ली, 1999, पृ. 33
16. मजूमदार, आर.सी., हिस्ट्री ऑफ़ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, 1957, पृ. 369
17. हार्डी, पीटर, द मुसलिम्स ऑफ़ ब्रिटिश इंडिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1972, पृ. 122